

ट्रंप की आशा के विपरीत, यूक्रेन-रूस युद्ध और सधन व खतरनाक हुआ

यूक्रेन ने रूस के भीतरी भागों में जबरदस्त ड्रोन-एटैक किया और बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुँचाया तथा गिरते हुए मलबे से काफी अफरा-तफरी मची रूस के शहर में

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के डॉनल्ड ट्रंप के वादे के विपरीत, अब यूक्रेन में लड़ाई और अधिक भयंकर हो गई है और यूक्रेन ने भी रूस में काफी अंदर तक जाकर भारी ड्रोन हमले किए हैं।

ट्रंप का प्रस्ताव था कि कम से कम एक माह के लिए सीमित युद्ध विराम हो, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर (ऊर्जा संयंत्रों) को निशाना नहीं बनाएँ। इसके विपरीत, रूस और यूक्रेन दोनों ने प्रतिशोध की नई और तीव्र भावना के साथ ऊर्जा केन्द्रों पर हमले किए हैं।

यूक्रेन ने रूस के भीतरी भागों में जबरदस्त ड्रोन हमले किए हैं, जिसने रूसियों को चकित कर दिया है। जवाबी कार्रवाही में रूस ने यूक्रेन के कुछ ऊर्जा संयंत्रों के साथ-साथ शहरों और नागरिक ठिकानों पर विनाशकारी हमले किए हैं।

यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूसी सेना ने सुमी और डोनेटस्क क्षेत्र में वोलो रोड क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों पर भारी हमले किए हैं। वहीं, यूक्रेन के कुछ ड्रोन हमलों की वजह से रूस में इमारतों को काफी नुकसान हुआ है और चारों ओर गिरते हुए

दूसरी ओर रूस ने बदले की भावना से यूक्रेन पर धावा बोला। कुर्स्क क्षेत्र में, जहाँ यूक्रेन ने रूस की काफी भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, वहाँ से, रूस की भारी गोलाबारी के दबाव में, यूक्रेन को लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छोड़कर पीछे हटना पड़ा।

ट्रंप ने यूक्रेन व रूस के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि 30 दिन का युद्ध विराम रहेगा तथा इस अवधि में दोनों देश एक दूसरे के बिजली संयंत्र आदि पर गोलाबारी नहीं करेंगे। पर, युद्ध विराम का प्रस्ताव, अस्वीकार सा ही रहा तथा दोनों देशों ने एक दूसरे के बिजली संयंत्रों आदि पर जमकर बमबारी की।

रूस का हमला इतना भयंकर था, बिजली के संयंत्रों व नागरिक प्रतिष्ठानों पर कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जैर्लेन्स्की, सीमा का दौरा करने को बाध्य हुए, सेना का मनोबल उंचा रखने के लिए।

मलबे ने जनता में व्यापक रूप से सार्वजनिक भय पैदा कर दिया है।

ट्रंप के सीमित युद्ध विराम प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए, रूसियों ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और नागरिक लक्ष्यों पर नए उन्माद के साथ फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न

मजबूर कर दिया है। रूस ने हाल ही में दावा किया है कि उसने 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है, जो पहले यूक्रेनी नियंत्रण में था।

इस नुकसान के कारण, सऊदी अरब के नेतृत्व वाली वार्ता में यूक्रेन की सौदेबाजी की स्थिति कमजोर हो गई है। वार्ता करने वाले अमेरिकी और यूक्रेनी दल इन रूसी क्षेत्रों को रूसियों के साथ सौदेबाजी के कार्ड के रूप में देख रहे थे। अब, यूक्रेनी पक्ष अपनी सौदेबाजी की ताकत को तेजी से खोता जा रहा है।

यह संभव है कि रूसियों ने डॉनल्ड ट्रंप और अमेरिकी दबाव को चुनौती देने के लिए कुछ सोच-समझ कर कदम उठाए हों। यह स्पष्ट है कि अमेरिका विभिन्न मोर्चों पर विभिन्न समूहों और ताकतों के दबाव में है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध वार्ता से अलग हो रहा है, क्योंकि वो अन्य हमलों और गतिविधियों के कारण स्वयं दबाव में है। लाल सागर क्षेत्र में हूली विद्रोहियों ने अलग-अलग फैले ठिकानों से अमरीकियों और इजरायल पर गंभीर हमला किया है। हूतियों ने अमेरिकी नौसेना के "हेरी एस. ट्रुमैन" विमानवाहक पोत पर मिसाइलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो अति.मु.सचिवों को सिविल कारावास

जयपुर, 22 मार्च। शहर के वाणिज्यिक न्यायालय क्रम-1 ने अर्बोर्ड राशि का भुगतान नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और भास्कर ए सावंत को तीन-तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी

वाणिज्यिक न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत को दो अलग-अलग मामलों में तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर ठेकेदारों को निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने का आरोप है।

गई है, जिस पर अदालत अगले सप्ताह सुनवाई करेगी।

जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय क्रम-1 ने ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने से संबंधित विवाद पर अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर यह आदेश दिया। नागौर मुकुंदगढ़ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 में सड़क कानिर्माण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पिछले वर्ष ओडिशा चुनाव से पूर्व तत्कालीन मु.मंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के बारे में कई चर्चाएं शुरु हुई थीं

कुछ ऐसा ही क्रम अब बिहार में चल रहा है और भारी अटकलबाजियाँ चल रही हैं मु.मंत्री नीतीश कुमार की मानसिक व शारीरिक "हेल्थ" के बारे में

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। गत वर्ष ओडिशा विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से विवाद पैदा हुए थे, बिल्कुल उसी तरह बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के "मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य" को लेकर एक अभियान जोर पकड़ रहा है।

राज्य में विधानसभा चुनाव इस वर्ष अक्टूबर-नवम्बर में होने हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की मानसिक-शारीरिक स्थिरता को लेकर पैदा हो रहे विवाद एन.डी.ए. गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के नज़दीक माने जाने वाले न्यूज चैनल, नीतीश के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न उठाते हुए कई कार्यक्रम प्रसारित कर चुके हैं। इन घटनाक्रमों से इन संदेहों को बल मिल रहा है कि नवम्बर में होने वाले चुनावों में भाजपा अकेले ही उतरेगी। पर इन विवादों के लिए खुद नीतीश ही जिम्मेवार हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक क्लिप में प्रधान सचिव दीपक कुमार के साथ बातें करते व टहलते लगाते हुए दिख रहे हैं जबकि उस समय राष्ट्रगान बज रहा था। यह

मजे की बात यह भी है कि चर्चाओं का यह अभियान उन चैनलों पर ज्यादा जोर-शोर से चल रहा है, जो भाजपा के नज़दीक माने जाते हैं।

इससे जनता यह कयास लगाने लगी है कि कहीं भाजपा, नीतीश से संबंध-विच्छेद करके अकेले ही चुनाव तो नहीं लड़ना चाहती, अक्टूबर-नवम्बर में प्रस्तावित असैम्बली इलैक्शन में।

शायद इन अटकलबाजियों के लिये स्वयं नीतीश ही जिम्मेवार हैं।

हाल ही में उनका सार्वजनिक आचरण कुछ अटपटा जरूर रहा है। पटना में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन के बाद, "जन-गण-मन..." के गायन के समय वे अपने सचिव व वरिष्ठ आईएस अधिकारी के साथ हंसते हुए, बतियाते हुए सभी चैनल्स पर दिखे।

इसी प्रकार, महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस, जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर, श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार, ताली बजाते दिखे थे। इसके अलावा वे आजकल यदा-कदा सार्वजनिक समारोह में, लोगों के, विशेषकर प्र.मंत्रीमोदी के पैर छूते हुए भी नज़र आ जाते हैं टी.वी. पर।

घटना पटना में आयोजित इंटरनेशनल जनवरी में भी कुमार ने एक विवाद खड़ा स्पोट्स कार्यक्रम की है। इससे पहले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

6 राज्यों के मुख्यमंत्री व प्रांतीय नेता एकत्रित हुए स्टालिन के निमंत्रण पर

इनका घोषित उद्देश्य था भारतीय गणतंत्र और संघीय ढांचे को बचाना

-लक्ष्मण वैकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। आंध्र प्रदेश को छोड़कर समूचा दक्षिण भारत शनिवार को चेन्नई में एकत्रित हुआ और "परिसीमन" कवायद, जिसे इन्होंने अनुचित व अन्यायपूर्ण करार दिया है, के खिलाफ विरोध जताया। इनका मत है कि परिसीमन से संसद में दक्षिण का प्रतिनिधित्व और महत्व कम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी तेलुगुदेशम और विपक्षी पार्टी वायएसआरसीपी दोनों ही भाजपा की गोद में बैठे हैं।

तकनीकी रूप से देखें तो परिसीमन के खिलाफ पहली जॉइंट एक्शन मीटिंग का विस्तार पूर्व और उत्तर तक हुआ, साथ ही इसमें ओडिशा से बीजू जनता दल और पंजाब से आम आदमी पार्टी ने भी शिरकत की। मीटिंग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बुलाई थी। इस विचार की सफलता और इसके क्रियान्वयन ने स्टालिन को राज्य

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जॉइंट एक्शन कमेटी मीटिंग को भारतीय गणतंत्र व संघवाद की रक्षा के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।

से बाहर भी बतौर नेता स्थापित कर दिया है।

भाजपा की स्थानीय इकाई ने मीटिंग स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे लहराए। उन्होंने स्टालिन व उनके सहयोगियों पर कावेरी और मुलाई पेरियार मुद्दे पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष अन्नमलाई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने केरल के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिसने तमिलनाडु को

मैडिकल कचरे का डंपआई बना दिया है और अपनी कमियाँ छुपाने के लिए वे व्यर्थ का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी हार तय है।

इसमें रोचक बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने अपने दो प्रतिनिधि मीटिंग में भेजे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस जानती है कि उत्तर भारत से उसे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां भाजपा का दबदबा है। यूपी में कांग्रेस पूरी तरह से सपा पर आश्रित है।

स्टालिन ने परिसीमन पर जॉइंट एक्शन कमेटी मीटिंग को भारत के संघीय ढांचे की सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक दिवस बताया वहीं अन्य सभी दलों ने लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन की निंदा की। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. पेपर लीक मास्टरमाइंड की साली फरार

जयपुर, 22 मार्च। प्रदेश में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पोर कालेर की साली प्रियंका गोस्वामी फरार हो गई है। प्रियंका गोस्वामी जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 18 मार्च को महिला ट्रेनी एसआई प्रियंका गोस्वामी को पृष्ठताछ के लिए आदेश

गहलोत सरकार के कार्यकाल में सबसे चर्चित पेपरलीक मामले की जांच जोर पकड़ रही है और जांच कर रही एसआईटी ने 15 से 20 ट्रेनी एसआई को शक के दायरे में लिया है।

जारी किया था। लेकिन 21 मार्च को वह गायब हो गई।

एसओजी एडीजी वीके सिंह ने बताया कि जब मास्टरमाइंड पोर कालेर से पृष्ठताछ की गई, तो यह जानकारी सामने आई कि करीब 15 से 20 ट्रेनी एसआई को पेपर पढ़ाया था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य छीने

सुप्रीम कोर्ट ने जाँच के लिए तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों का पैनल बनाया है

नई दिल्ली, 22 मार्च। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी केश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कार्य से सस्पेंड कर दिया है। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएँगे। न्यायपालिका का पक्ष सबके सामने रखने के लिए सोजेआई संजीव खन्ना ने सारा रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सब रिपोर्ट पब्लिक होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने 21 मार्च को इंटरनल इन्क्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सोजेआई संजीव खन्ना को सौंपी थी। शनिवार शाम सोजेआई ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मामले का सारा रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।

इसी के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब, जाँच समिति की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

ज्ञातव्य है कि गत 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगने के दौरान कथित तौर पर भारी मात्रा में केश मिला था, इसको लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है।

तीन सदस्यीय समिति बनाई और दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक काम न सौंपने को कहा है। सोजेआई संजीव खन्ना ने बड़ा कदम उठाया है। अब इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। दिल्ली उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।

सोजेआई संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए जो तीन सदस्यीय समिति गठित की है, उसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के बंगले पर 14 मार्च की रात आग लगने के बाद केश बरामद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)





हार्श केमिकल हटाइए, पतंजलि से कुदरती स्वच्छता व सुन्दरता पाइए।
पतंजलि नेचुरल फेसवॉश एवं हर्बल बाथ सोप की रेंज



हल्दी, चन्दन, एलोवेरा, नीम, गुलाब एवं 80% से अधिक प्राकृतिक तत्वों से निर्मित पतंजलि हर्बल बाथ सोप अपनाइए।

हानिकारक केमिकल रहित प्राकृतिक तत्वों से तैयार, हर प्रकार की त्वचा के लिए पतंजलि फेस वॉश की रेंज।